प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की

8 फरवरी,2015

"टीम इंडिया" से प्रधानमंत्रीः

- **सहकारितापूर्ण, प्रतिस्पर्द्धी संघवाद का प्ररूप तैयार करें; प्रगति और खुशहाली का साझा मार्ग तैयार करें**
- **हमारी सबसे बड़ी चुनौती गरीबी उपशमन की है। आइए, हम वृद्धि की गति को तेज़ करें**
- **आइए, हम अपने सभी मतभेदों को भुलाकर निवेश, वृद्धि, रोज़गार सृजन तथा खुशहाली के लिए काम करें।**
- **सबके लिए समान नीति की योजना छोड़ दी जाएगी; स्कीमों के बीच बेहतर तालमेल तथा राज्यो की आवश्यकता का अधिक ध्यान रखा जाएगा**
- **नीति आयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदें सदस्य राज्यों की साझा परियोजनाओं में तेज़ी ला सकती हैं**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की ताकि सहकारितापूर्ण संघवाद के प्ररूप को मज़बूत करने के लिए वे केंद्र के साथ मिलकर काम करने के प्रयोजन से टीम इंडिया यानी केंद्र और राज्य अपने मतभेदों को भुलाकर साथ आएं और प्रगति तथा खुशहाली का साझा खाका तैयार करें।

नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की शासी परिषद् राष्ट्रीय उद्देश्य को आगे ले जाने में सहायक होगी क्योंकि "यह हमारा साझा उद्देश्य" है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तब तक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक इसके राज्यों में भी प्रगति न हो। उन्होंने यह भी कहा कि सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप, सभी राज्यों को साथ लाने का विचार है। उन्होंने कहा कि वे "सहकारितापूर्ण, प्रतिस्पर्द्धी संघवाद" की भावना को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को बेहतर शासन की दृष्टि से प्रतिस्पर्द्धा करते हुए देखना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत के प्रति दुनिया का नज़रिया बदल रहा है, किंतु अब भी "हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि गरीबी किस प्रकार समाप्त की जाए।" उन्होंने कहा कि वृद्धि के बगैर न तो रोज़गार सृजित हो सकता है और न ही गरीबी मिटाई जा सकती है। उन्होने यह भी कहा कि हमें "सबसे पहले अपनी वृद्धि दर तेज़ करने का लक्ष्य रखना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर निर्णय न होने के कारण परियोजनाएं अटकी रहती हैं और परियोजना किसी भी मंच पर किसी भी चरण में अटक जाती है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को परियोजनाओं के लाभ नहीं मिल पाते और लागत भी बढ़ जाती है। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें जिनके कारण परियोजनाओं का काम धीमा पड़ता है। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे निवेश, वृद्धि, रोज़गार सृजन तथा खुशहाली पर अधिक ध्यान

दें। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि लंबित मामलों पर नज़र रखने तथा उसके सहज समाधान के लिए राज्य सरकार एक-एक अधिकारी को चिह्नित करें ताकि परियोजनाओं का कार्यान्वयन तेज़ हो सके।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि केंद्र सरकार को राज्यों को आर्थिक, प्रौद्योगिकीय तथा ज्ञान की दृष्टि से सशक्त करना चाहती है ताकि वे बेहतर ढंग से योजना तैयार कर सकें तथा उससे भी बेहतर तरीक़े से उसका कार्यान्वयन कर सकें।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नीति आयोग की स्थापना संबंधी मंत्रिमंडल संकल्प में, ऐसी क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है जिनके पास निश्चित समय-सीमा के लिए विनिर्दिष्ट अधिदेश हों। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये परिषदें साझा समस्याओं से जूझ रहे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सहयोग बढ़ा सकती हैं अथवा ऐसे विवादों को सुलझा सकती हैं जिनके कारण प्रगति में विलम्ब होता है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं सदस्य राज्यों के बीच यात्रा, परिवहन तथा पर्यटन से जुड़ी साझा परियोजनाओं में तेज़ी ला सकती हैं।

प्रधानमंत्री ने यह आशा भी व्यक्त की कि नीति आयोग की व्यवस्था के माध्यम से, भारत सबके लिए समान नीति वाली स्कीमों से आगे बढ़ सकता है और स्कीमों तथा राज्यों की आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल कायम कर सकता है। उन्होंने कहा कि संघवाद तभी ठीक से काम कर सकता है, जब राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य भी अपनी भूमिका का निर्वाह करें। उन्होंने कहा कि सहकारितापूर्ण संघवाद की सफलता के लिए आवश्यक है कि राज्य साझा राष्ट्रीय उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में अपने मार्ग के प्रति समर्पित रहें और फिर उस समर्पण को कार्यरूप देकर दिखाएं।

एक विचार मंच के रूप में नीति आयोग की भूमिका की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के लिए एक दूसरे से सीखने, आपस में तथा केंद्र के साथ मिलकर काम करने की गुंजाईश काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य की सर्वोत्तम कार्यशैली को दूसरे राज्य अपना सकते हैं तथा एक ऐसा पोर्टल बनाया जा सकता है जिस पर राज्य के अधिकारी अपने अनुभव साझा करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित से बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई है। उन्होंने मौजूद गणमान्य व्यक्तियों से इस बात पर चर्चा करने का अनुरोध किया कि योजना प्रक्रिया को किस प्रकार नया रूप दिया जाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि "सुशासन पर अधिक बल दिया जाना समय की मांग है"। उन्होंने यह भी कहा कि "हम जो कुछ भी करें,वह सुविचारित हो, अच्छी तरह कार्यान्वित हो तथा उसका परिणाम अपेक्षानुरूप ही हो।"

चर्चा का समन्वयन वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने किया तथा बैठक का शुरूआती संबोधन नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविन्द पानगड़िया ने दिया।

*****

राष्ट्रीय विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगपूर्ण प्रतियोगी संघवाद के विजन के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा टीम इंडिया पर ध्यानकेन्द्रण

नीति आयोग की शासी परिषद् की बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नवगठित नीति आयोग की शासी परिषद् की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

योजना आयोग के स्थान पर, 01 जनवरी, 2015 को नीति आयोग गठित किया गया है। सरकार ने नीति आयोग का गठन करने वाले संकल्प को अधिसूचित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ इसके उद्देश्यों और ढांचे का निर्धारण करता है। इस अधिसूचना के अनुसार, नीति आयोग में इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री शामिल हैं, इसकी शासी परिषद् में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल, संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले दक्ष, विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति और पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा शामिल है।

पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिवालय शामिल है।

श्री राजनाथ सिंह- गृह मंत्री, श्री अरुण जेटली- वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु- रेल मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह- कृषि मंत्री को पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, श्री नितिन जयराम गडकरी- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री थावर चन्द गहलोत- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी- मानव संसाधन विकास मंत्री को विशेष आमंत्रितों के रूप में नामित किया गया है।

सरकार ने डॉ. अरविन्द पानगड़िया को उपाध्यक्ष के रूप में और श्री बिबेक देबरॉय और डॉ. वी. के. सारस्वत को पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है। श्रीमती सिंधुश्री खुल्लर को नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

स्मरण कराया जाता है कि 07 दिसम्बर, 2014 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपालों के साथ अपनी परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास एजेंडा की ओर समन्वित रूप से कार्य करने के लिए टीम इंडिया गठित करने के विजन की रूपरेखा दी थी।

शासी परिषद् की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने इस विजन, जो सहयोगपूर्ण संघवाद की संकल्पना का मूर्तरूप है, की और अधिक व्याख्या की। इस विषय पर, प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वे राज्यों के विकास के लिए उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के पक्षधर हैं।

यह इंगित किया गया कि नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस ढांचे के माध्यम से केन्द्र, सहयोगपूर्ण संघवाद के मार्फत राज्यों की तीव्र प्रगति को संभव बनाएगा। ध्यान देने योग्य विशिष्ट मुद्दों और राज्यों के तुलनात्मक सबल पक्षों के आधार पर विचार-विमर्श के लिए संरचनात्मक तंत्र के संबंध में विभिन्न सुझाव मांगे गए। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने हेतु क्षेत्रीय परिषद् का गठन करने के संबंध में राज्यों की राय मांगी गई।

प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के तहत तीन उप-समूह गठित करने की घोषणा की; सभी राज्यों को नीति आयोग के तत्त्वावधान में दो कार्यदल गठित करने के लिए कहा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि नीति आयोग निम्नलिखित विषयों पर मुख्यमंत्रियों के **तीन उप-समूहों** का गठन करेगाः

- **66 केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों का अध्ययन करने और यह सिफारिश करने कि किन स्कीमों को जारी रखा जाए, किन स्कीमों को राज्यों को अंतरित किया जाए और किन स्कीमों की कटौती की जाए, से संबंधित उप-समूह।**
- **यह सिफारिश करने से संबंधित उप-समूह कि नीति आयोग कौशल विकास और राज्यों में कुशल जनशक्ति के सृजन को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है।**
- **स्वच्छ भारत के प्रति प्रतिबद्धता को सतत आधार पर हमारे जीवन का एक भाग बनाना सुनिश्चित करने के लिए विकसित किए जाने वाले संस्थागत तंत्रों और प्रौद्योगिकी संबंधी सुझावों का निर्णय करने संबंधी उप-समूह।**

नीति आयोग की शासी परिषद् की पहली बैठक में अपनी समापन टिप्पणी में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को नीति आयोग के तत्त्वावधान में **दो कार्यदल** गठित करने के लिए भी कहा। एक कार्यदल गरीबी उपशमन पर ध्यान केंद्रित करेगा और दूसरा, राज्य में कृषि के भावी विकास और इस संबंध में केन्द्र, राज्य की किस प्रकार सहायता कर सकता है, पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मुख्यमंत्रियों द्वारा अपनी अधिमान्यताएं इंगित करने के बाद इन उप-समूहों के सदस्यों के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से शौचालयों का निर्माण और स्तरोन्नयन करने के लिए स्कूलों की आगामी छुट्टियों का लाभ उठाने का आग्रह किया ताकि सभी स्कूलों के लिए शौचालय के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि 2019 तक, स्वच्छता संबंधी कार्यकलापों के लिए, एमपीएलएडी और एमएलएएलएडी स्कीमों के तहत निधियों का कुछ भाग उद्दिष्ट किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने, बैठक में भाग लेने वाले सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा बैठक के दौरान व्यक्त किए गए विचारों और विजन में उनके द्वारा दर्शायी गई टीम भावना की सराहना की।